ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292, REG. No.: 561/2013-2014 Vol.-1, No.-1, PP-348-351, YEAR-2014

घरेलू आतंक की चुनौती : नक्सलवाद

❑ जगदीश कुमार

सार– *वर्तमान में राष्ट्र आन्तरिक सुरक्षा की जटिल समस्याओं एवं खतरों से ग्रसित है। नक्सलवाद से असुरक्षा का प्रसार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। नक्सलवाद हिंसा, गरीबी, बेकारी और अन्याय के आक्रोश से उपजा विद्रोह है। हिंसा, हत्या, प्रतिशोध की भावना से जनित और इनके इस इरादे में जो भी अवरोध पैदा करता है। उसका अन्त कर दिया जाता है। इन कार्यवाहियों को अंजाम देने वाले विद्रोहियों को नक्सलवादी कहा जाता है। नक्सलवादी हिंसात्मक आन्दोलन वर्ग संघर्ष से प्रेरित होकर माओं के दर्शन में विश्वास करके हिंसा का समर्थन करते है। नक्सलवादी आन्दोलन की शुरूआत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नेपाल की सीमा से लगे नक्सलबाड़ी नामक एक छोटे से क्षेत्र में 25 मई 1967 की एक घटना के साथ हुई। इसके जनक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल थे।[1] यह आन्दोलन "सत्ता बन्दूक की नली से निकलती है।" को आदर्श मान प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर दिन प्रतिदिन हिंसा के दायरे को बढ़ा रहा है। इन नक्लसवादियों ने अपने शुरूआत से लेकर वर्तमान समय तक आन्तरिक सुरक्षा को कमजोर करते हुये अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे है। जिसका परिणाम वर्तमान में 20 प्रान्तों के लगभग 223 जिले नक्सली हिंसा से प्रभावित है।[2]*

नक्सली आन्दोलन के सूत्रधार चारू मजूमदार ने कहा था कि 'नक्सलवादी है और हमेशा रहेगा। ऐसा इसलिए हैं क्योंकि यह अदृश्य मार्क्सवाद, लेनिनवाद माओवादी विचारधारा पर आधारित है। हम यह जानते है। कि जैसे ही हम आगे बढ़ेगें हमें बहुत सारे अवरोध मिलेंगे लेकिन नक्सलवादी नहीं मरेगा।[3] नक्सली हिंसा की घटनाऐं न केवल संख्या में बढ़ी है बल्कि उनकी तीव्रता में बढ़ोतरी हुई है यदि हम आंतकवाद को बाहरी संकट मान लें तो साम्प्रदायिकता के बाद नक्सलवाद हमारा सबसे बड़ा आन्तरिक सुरक्षा के लिये संकट है। आज देश के कई राज्यों में नक्सली हिंसा की घटनाएँ राज्य प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। नक्सली खुलेआम रेल की पटरियों और रेलवे स्टेशनों को बम विस्फोट कर उड़ा देते है। वे पुलिस थानों और सुरक्षा बलों पर भी हमला करते है। नक्सली समस्या देश के इन इलाकों में मौजूद भयानक गरीबी एवं असमानता की उपज है जो हिंसा राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित कृत्रिम प्रयासों को परिणाम है यदि गरीबी, बेकारी और सामाजिक – आर्थिक अन्याय कायम नहीं होते है। और हिंसा के पनपने के लिए जमीन तैयार न की गई होती तो यह समस्या जड़ नहीं पकड़ती।[4] सत्तर के दशक के नक्सलवादियों से लेकर के पिछले दो दशकों में बेदखली के मामले जैसे–जैसे बढ़ रहे हैं। उसी अनुपात में नक्सलवाद का दायरा भी बढ़ रहा है। इस संदर्भ में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। कि नक्सलवादियों का आन्दोलन उल्फा व बोडो की तरह न तो कोई पृथकतावादी आन्दोलन है और न ही जाति धर्म व अर्थपरक, परन्तु यह बात भी गौर करने वाली है कि नक्सली संगठनों को स्थानीय स्तर पर पृथकतावादी आन्दोलन संगठनों से भी अधिक समर्थन प्राप्त है।

वर्तमान में देश में लगभग 56 नक्सली गुट मौजूद है जिनकी संख्या 50 हजार से भी अधिक है इनमें 20,000 से भी अधिक आधुनिक हथियारों से लैस विद्रोही है।[5] देश के वनों का एक तिहाई से भी

असि0 प्रोफेसर– शिक्षाशास्त्र विभाग, श्री रामेश्वरदास अग्रवाल कन्या पी.जी. कॉलेज, हाथरस (उ0प्र0), भारत

अधिक भाग इनके कब्जे में है। स्त्री पुरूष व बच्चे तक इन गुटों के सक्रिय सदस्य हैं यह मूल से आस्ट्रो एशियाटिक ट्राबिडियन है। यह गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाले लोग है। इसमें अधिकांश भूमिहीन कृषक गरीब व बेरोजगार युवा है जो जंगली जीवन जीने को मजबूर हैं। आंतरिक सुरक्षा का यह खतरा अचानक ही नहीं उभरा है। भारत में जटिल किस्म के इस तरह के छोटे संघर्ष और आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाले विद्रोह के तीन मुख्य तत्व है। पहला तत्व है 1948 से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का उभार, दूसरा है 1950 में पूर्वोत्तर में विद्रोह घटनाओं में तेजी और तीसरा तत्व है 1960 के दशक में नक्सल और माओवादी आन्दोलन जो कि अब काफी विकृत रूप ले चुका है।[6] नक्सली आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए कोडापल्ली सीतारमैय्या ने नेतृत्व पी0डब्लू0जी0 के संगठन में कई तत्वों व उद्देश्यों को समाहित किया गया जिसमें कि सरकारी अधिकारियों का अपहरण कर अपने गिरतार साथियों को जेल से रिहा कराने की नक्सल गुरिल्ला रणनीति प्रमुख रही है। 1980 के दशक के अन्तिम दौर में पी0डब्लू0जी0 के गुरिल्ला ने छः बड़े शासकीय अधिकारियों का अपहरण किया था। नक्सल गुरिल्ला रणनीति में आंतक और अपहरण एक आवश्यक तत्व बन गये है। खुद को माओं का अनुयायी करार देने वाले नक्सलवादियों ने हिंसा और आंतकवाद को अपना रखा है। नक्सल रणनीति कॉमरेड माओ की तुलना में लैटिन अमेरिकी कॉमरेड चे ग्वारा के फोको टैररिज्म के कहीं अधिक निकट है, जिसमें प्रत्येक आंतकवादी कार्यवाही को विचाराधात्मक प्रोपेगेंड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।[7] 1980 में के0एन0 रामचन्द्रन के नेतृत्व में (एम0एल0) रेड़ लेग का गठन किया गया। 1982 में सी0पी0आई0 (एम0एल0) लिबरेशन की दिल्ली में आयोजित नेशनल कांग्रेस में इडियन पीपुल्स फ्रंट लांच किया गया। साल के अन्त में तात्कालिक बिहार के गिरिडीह जिले में सी0पी00आई0 एम0एल0 की तीसरी कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें चुनावों में भाग लेने का निर्णय लिया गया। जून 1984 के आप्रेशन ब्लू स्टार और 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद फैले देशव्यापी सिख विरोधी दंगों के समय सी0पी000आई0 (एम0एल0) और अन्य क्रान्तिकारी ने सिखों को किसान आन्दोलन से जोड़ने की कोशिश की। 1985 में पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के असम विधानसभा की एक सीट पर चुनाव जीतने के साथ ही सी0पी0आई0(एम0एल0) कैडर की विधानसभा कार्यक्षेत्र में पहली दस्तक हुई।[8] 90 के दशक में माओवादी गतिविधियों का विस्तार तेजी से अल्पविकसित एवं जनजातीय क्षेत्रों में हुआ। सितम्बर 2004 में दो संगठनों पी.डब्लू.जी. एवं एम.सी.सी. ने आपस में विलय करते हुए भारतीय कम्यूनिट पार्टी (माओवादी) नाम से नये संगठन को जन्म दिया जिसके परिणमस्वरूप यह राज्यों के लिए कानून व्यवस्था हेतु चुनौती बना हुआ है। नक्सलवाद केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है बल्कि यह समस्या मानव व्यवहार से जुड़ी है। नक्सली समस्या के पीछे गहरी सामाजिक आर्थिक असमानताएं छिपी हुई हैं। अब तक केन्द्र से लेकर राज्य सरकारों ने इस व्यवस्था को कानून व्यवस्था का मामला मानकर हल करने की कोशिश की है। यही कारण है कि आज लगभग साढ़े तीन दषकों के बाद भी यह समस्या जस की तस बनी हुई है।[9]

नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित झारखण्ड, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से लेवी से सलाना 1500 करोड़ रूपये की आमदनी होती है।[10] भाकपा (माओवादी) झारखण्ड़ में अब भी प्रमुख नक्सली समूह पर छिटपुट समूहों ने भी अपहरण लूटपाट व मादक पदार्थों की तस्करी के अलावा लेवी लगाने कका काम षुरू किया। नक्सलियों की कुल अनुमानित संख्या पैंतालीस हजार के करीब है। नक्सलियों द्वारा बिहार झारखण्ड़ और मध्यप्रदेश में अंजाम दी गई। श्रृंखलाबद्व हिंसक घटनाओं के चलते हाल के महीनों में इस बारे में काफी कुछ लिखा गया है। बिहार में इनका पसंदीदा निशाना रेलें है। यहां नक्सलियों की हिंसा का असर तब

देखने को मिला। जब 4 अप्रैल 2006 को उन्होंने स्थानीय माओवादी नेताओं की गिरतारी के विरोध में बंद का आह्वान किया। कई इलाकों में तो इस दिन बसें और रेलें तक भी नहीं चली। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक नक्सलवादियों ने अपना प्रभाव 230 जिलों तक बढ़ा लिया है और वे काठमान्डू से केरल तक एक रेड कॉरिडोर बना देना चाहते है।

नक्सली आक्रमणात्मक कार्यवाही माओ के सिद्धान्तों से प्रेरित होकर अपनी हिंसात्मक गतिविधि के लिए मनोवैज्ञानिक स्थितियों से लड़ते हैं जो सामान्य रूप से नक्सली रात्रि से स्वतंत्र गतिविधियां करते हैं। नक्सली माओ के सिद्धान्त की तीनों स्थितियां (सामरिक सुरक्षात्मक, सामरिक समता, सामरिक आक्रामक) से अपनी कार्यवाही का संचालन करते हैं। नक्सलियों ने गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाकर एवंज न समर्थन प्राप्त करके अपनी कार्यवाहियां शुरू की। यह स्त्रातेजी इस तथ्य पर आधारित थी कि यदि पानी से भरी एक बाल्टी में तेल का छिड़काव किया जाये तो तेल के घब्बे बन जायेंगे। लेकिन यदि पानी को हिलाकर थमने दिया जाए तो तेल का एक बड़ा घब्बा सतह पर तैरने अर्थात् अनेक छोटे–छोटे प्रभाव क्षेत्रों का निर्माण करके एक अनुकूल समय पर एक इकाई के रूप में गठित हो जाना नक्सलियों की मुख्य रणनीति थी। नक्सली मनोवैज्ञानिक पद्वति से लड़ी जाने वाली इसमें लड़ाई में प्रचार अफवाह बुद्धि परिवर्तन जैसे तरीकों को अपनाते है। नक्सल प्रभावित राज्यों में रह रहे नक्सली खूनी सलाम के रूप में हैरतकारी महलों को अंजाम देते है। जिनकी दुःस्वप्नों में भी कल्पना करना कठिन होगा चाहे वह दंतेवाड़ा में नक्सली आक्रमण 06.04.2011 की व्यापक हिंसात्मक नक्सली कार्यवाही थी जिसमें कि 76 अर्द्धसैनिक बल के जवान मारे गये हो या 20 मई 2010 को माओवादियों ने पूर्व मध्य रेलवे के मुजफरपुर नरकटियागंज के तहत आने वाले बिहार के दिघवाड़ा और पीपरा के बीच रेल लाइनों पर विस्फोट किया। जिसके बाद एक मालगाडी के 14 तेल के टैंकर पटरी से उतर गए और उनमें आग लग गई। नक्सलियों द्वारा किये गये हमलों में आर्थिक नुकसान भारतीय सरकार को उठाना पड़ रहा है।

नक्सल समस्या को देश का सबसे बड़ा खतरा बता चुकी सरकार इससे निपटने में एक कदम आगे बढ़ती दिखती है तो दो कदम पीछे हट जाती है। आतंक का यह चेहरा देश का कई इलाकों में अपना वर्चस्व बढ़ाता दिखा रहा है। इसी भीषण समस्या के दायरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 16 सालों में जम्मू कश्मीर में आंतकवादी हिंसा और पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवाद समेत अन्य क्षेत्रों में आंतकी या हिसांत्मक घटनाओं में मारे गए कुल लोगों की संख्या 54796 है जबकि केवल नक्सली हिंसा में पिछले छह सालों में केवल 4193 लोग अपनी जान गंवा चुके है।[11] नक्सलियों ने हिंसा को तेज करना, राष्ट्र विरोधी तत्वों से गठजोड़ और जन समर्थन जुटाने की कोशिश आदि हथकंडो को अपनाया है केन्द्र सरकार ने नक्सली हिंसा को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों को बारूदी सुरंग प्रुफ वाहन उपलब्ध कराने के साथ बीमा योजना भी शुरू की गई है जबकि नक्सलियों के सरेन्डर करने वालों को पुर्नवास योजना व नक्सल प्रभावित इलाकों में बेरोजगारों को काम देने का प्रयास किया जा रहा है। समाज एक तबका नक्सलियों के खिलाफ फौज उतारने की वकालत करता है। लेकिन यह समझदारी नहीं होगी। वैसे भी देश के अंदरूनी हिंसक अंतर्विरोधों में फौज का बार बार इस्तेमाल लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है सवाल यह है कि पुलिस के खुफिया नेटवर्क को सक्षम बनाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती। भारत में एक लाख की जनसंख्या पर मात्र 10 खुफिया ऐजेंट तैनात है, जबकि अमेरिकी, रूस और चीन में इनकी तदात एक लाख पुलिस कर्मियों की तैनाती है, जबकि एक लाख पर 500 पुलिस बल की तैनाती आवश्यक है नक्सल विस्तार को रोकना है तो पुलिस बलों को अत्यन्त सक्षम तौर पर कारगर बनाने की बेहद जरूरत है। दूसरी ओर आदिवासियों और किसानों के अंसतोष को भी कम करना होगा। कॉरपोरेट सेक्टर को किसानों

के खिलाफ खड़ा करने के बजाय किसानों का सहयोगी बनाना चाहिए। कॉरपोरेट क्षेत्र को ही आदिवासियों के पुर्नवास की जिम्मेदारी देनी चाहिए। तभी नक्सल आन्दोलन पर अंकुश लगाया जा सकता है।

नक्सलवाद के समूल नष्ट करने में सबसे अधिक आवश्यक है कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में विकास व रोजगार के कार्यक्रमों का संचालन करें और वहाँ की जनता को उसी क्षेत्र में व्याप्त उद्योगों में रोजगार दें जिससे कि वह उस क्षेत्र में वाह्य लोगों पर अत्याचार नहीं करेंगे। सरकार को पर्याप्त प्रयासों से कृषि सिंचाई हेतु नहरों व बांधों का निर्माण कर कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि नक्सलवाद आन्दोलन की आधार भूमि ही गरीबी एवं असमानता की गहरी खाई है। अतः नक्सवाद को समाप्त करने के लिए इन आधारभूत समस्याऐं के साघनों एवं आर्थिक स्थिति को सृदृण आरक्षण सुविधा के अभाव को सुलझाना होगा सम्भवतः किसी भी समस्या ससे निजात पाने के लिए उसकी मूल समस्याओं का निदान करना जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ वामपंथी उग्रवाद को प्रोत्साहन संरक्षण प्रदान कर रहे है। उनके विरोधी शक्तियाँ का दमन करना होगा। जिससे कि इन क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रमों का संचालन किया जा सके स्पस्ट है कि जो वर्तमान योजनाऐं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के क्रियान्वित की जा रही है या उनसे जिन्हें लाभ प्राप्त हो वह इस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाये कि जिनका लाभ गरीब व शोषित लोगों को अवश्य लाभ प्राप्त हो। 21 वीं शताब्दी में भारत को विकसित शक्तिशाली राष्ट्र बनने लिए वामपंथी उग्रवाद पर विजय हेतु दृढ़ राजनैतिक सैनिक स्त्रातजी अपनानी होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डा0 पी0 के0 अग्रवाल 'नक्सलिस्म काजेज् एण्ड् क्यौर मानस पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2010 पेज नं0 16.
2. 30 ईयर ऑफ नक्सलवार, न्यू विस्टास पब्लिकेशन,कवर पेज।
3. जौहरी जे0सी0 नक्सलाइट पाजिटिक्स इन इंड़िया (द इन्स्टीट्यूट ऑफ कन्सटीट्यूसनल एण्ड् पार्लियामेन्टरी स्ट्डीज : न्यूयार्क, 1972).
4. दैनिक जागरण, 26 जून 2009.
5. दैनिक जागरण, 29 मई 2010.
6. दैनिक जागरण, 30 जून 2009.
7. अमर उजाला, 13 मार्च 2011.
8. डा0 एस0 के0 मिश्रा "नक्सलवाद" के0डब्लू0 पब्लिशर प्राइवेट लि0,नई दिल्ली, 2010,पेज 31.
9. इण्डिया टुडे, मार्च 2007 पृष्ठ 23.
10. इण्डिया टुडे, मार्च 2007 पृ.35.
11. दैनिक जागरण, 29 मई 2010.